

बख्शीश सिंह धालीवाल

बनाम

पंजाब राज्य

31 अगस्त 1966

(वी. रामास्वामी, वी. भार्गव और रघुवर दयाल, जे.जे.)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, धारा 233, 234, 197, 342- आरोप तथा विचारण का संयोजन सरकारी अधिकारी को साथ संयुक्त विधारण जिनकी अभियोजन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है-विचारण की वैधता अभियुक्त का परीक्षण-साक्ष्य की प्रत्येक वस्तु को मुल्जिम को सामने रखने की आवश्यकता है या नहीं।

भारतीय दंड संहिता, धारा 417, 420- सरकार को बिल प्रस्तुत किये गये सरकारी अधिकारियों द्वारा बेईमानी से स्वीकृत -भुगतान चाहे मिथ्या बिल प्रस्तुत करने का परिणामस्वरूप हो- अपराध अन्तर्गत धारा 417 अथवा धारा 420 ?

1943 का अध्यादेश 29 भारत सरकार अधिनियम, 1935 की 10 वीं अनुसूची की धारा 72 भारत और बर्मा (आपातकाल प्रावधान अधिनियम) 1940 (3 एवं 4 जियो 6. अध्याय 33), धारा 1(3)- पंजाब अध्यादेश

1946 का iii धारा 3(3)- पंजाब एक्ट 1950 का x - विशिष्ट अधिकरण का गठन, संचालन तथा पुनर्गठन।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम् 1872 धारा 35-युद्ध डायरीज का सेना अधिकारी द्वारा रखरखाव साक्ष्य में ग्राह्य है अथवा नहीं।

जिसने जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शिमला में कार्यरत बर्मा की इवेक्यू सरकार के समक्ष मिथ्या बिल प्रस्तुत करने के आरोप के संबंध में अपीलार्थी, एक ठेकेदार का विचारण अपराध अन्तर्गत धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के तहत किया गया।

उक्त आरोपों के सम्बन्ध में अपीलार्थी के विरुद्ध 10 आरोप विरचित किये गये तथा चार विचारण किये गये। उक्त अपराधों के संबंध में विशेष अधिकरण द्वारा उक्त सभी 10 आरोपों में अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें केवल तीन के संबंध में दोषी ठहराया।

अभिनिर्धारित: (i) एक कवरिंग लेटर के साथ बीस बिल भेजकर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता ने केवल एक ही अभ्यावेदन बनाया, जिसमें कई कार्यों तथा कच्चे माल की आपूर्ति से संबंधित दावा था। एक अभ्यावेदन, जो कि भिन्न-भिन्न कार्य और भिन्न-भिन्न सामग्री की आपूर्ति से संबंधित था, प्रत्येक कार्य और आपूर्ति के संबंध में पृथक पृथक

अभ्यावेदन होगा। अभिनिर्धारित किया गया कि चार पृथक-पृथक विचारण पृथक अभ्यावेदन के संबंध में सही था। {215 एच, 216 डी}

(ii) जब दो जगह पर आपूर्ति करने के संबंध में एक दावा किया गया था, तो ऐसी स्थिति में उसके संबंध में केवल एक ही आरोप हो सकता था, तथा दो अन्य आरोपों के साथ ऐसे आरोप का विचारण उचित था। {216 जी}

(iii) ऐसे अधिकारी, जिन्होंने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये मिथ्या बिलों का सत्यापन किया, निश्चित रूप से अपीलार्थी को दुष्प्रेरण करने के जुर्म में दोषी ठहराया जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी को किए गए भुगतान अपीलार्थी द्वारा स्वयं या उसके बिलों से किये गये अभ्यावेदन से संबंधित और उत्प्रेरित नहीं थे। वास्तव में, यह अपीलार्थी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन थे, जो वास्तव में, यह अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल उसके अभ्यावेदन थे जिनकी परिणति अंततः बर्मा सरकार द्वारा अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए दावों को पूरा करने के लिए धन देने के रूप में हुई। यह अभिनिर्धारण कि अपीलकर्ता उक्त परिस्थितियों में छल कारित करने का दोषी था, पूर्णतः उचित था। {217 डीजी}

(iv) प्रत्येक मामले में जहा संपत्ति किसी छल कारित करने वाले व्यक्ति द्वारा वितरित की जाती है, वहां हमेशा एक ऐसा चरण होना चाहिये

जब व्यक्ति अपने द्वारा किये गये मिथ्या अभ्यावेदन को स्वीकार करने पर संपत्ति देने का मन बना लेता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऐसे मामलों में अपराध करने वाला व्यक्ति धारा 417 भारतीय दण्ड संहिता के तहत सामान्य छल के लिये ही विचारित किया जाये और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के तहत विचारण नहीं चलाया जा सकता है क्योंकि छल कारित करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसा करने में लेने के बाद अपनी सम्पत्ति बेच दी। {218 बी}

(v) अपीलकर्ता का उन अधिकारियों के साथ संयुक्त विचारण, जिन्होंने अपीलकर्ता के बिलों को मंजूरी दी, केवल इस कारण दूषित नहीं होगा कि धारा 197 दण्ड प्रक्रिया संहिता के विधिक प्रावधानों की पालना नहीं हुई क्योंकि यह अधिकारी जिसने छल का दुष्प्रेरण किया, उसका कृत्य अपने लोक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करने की श्रेणी में नहीं आता। {219 डी}

के. सतवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य ख¹1960, 2 एस.सी.आर. 89, विश्वास जताया गया सुनील कुमार पॉल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 706, एवं स्वीकार किया गया

अपीलकर्ता के विचारण को उक्त अधिकारी के विचारण से अलग करने के बाद डीनाँवो विचारण की आवश्यकता नहीं थी। जहां तक अपीलकर्ता

का संबंध है, सम्पूर्ण विचारण उसके उपस्थिति में रहते हुये हुआ और यह तथ्य कि उक्त अधिकारी पर कुछ समय के लिये अपीलकर्ता के साथ संयुक्त रूप से विचारण चलाया गया था, इससे अपीलकर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। {219 जी}

(vi) 1943 का अध्यादेश 29 जिसके तहत गठित विशेष अधिकरण, गठित होने के छह माह के भीतर समाप्त नहीं हुआ था। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 की नवीं अनुसूची की धारा 72 में निहित प्रावधान से प्रभावित नहीं था क्योंकि धारा 72 के संचालन को भारत और बर्मा (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम 1940 से निलंबित कर दिया गया था। अध्यादेश समाप्त हो गया। जैसा कि जे.के. गैस प्लांट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (रामपुर) लिमिटेड और अन्य बनाम द किंग एम्परर, 30-09-1946 को इसके बाद अधिकरण द्वारा पूर्णरूप से 1946 के पंजाब अध्यादेश iii तथा 1950 के पंजाब अधिनियम x के तहत कार्य किया। {220 डी, ई}

(vii) केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब अध्यादेश iii की धारा 3(3) के तहत अधिसूचनाएं जारी की गईं तथा 1943 के अध्यादेश की धारा 11 और धारा 4 (3) (3) के अन्तर्गत नियम बनाये गये, जो कि अधिकरणों पर लागू हुये। जब तक कि पंजाब अध्यादेश के तहत पंजाब सरकार द्वारा अधिक्रमित या संशोधित नहीं कर दिये जाये। परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार द्वारा 1943 के अध्यादेश की धारा 3 के तहत विशेष अधिकरण के गठन

की जारी की गई अधिसूचनाएं पंजाब सरकार द्वारा अधिक्रमित या संशोधित किया जा सकता है। जब पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दो मूल सदस्यों के स्थान पर दो सदस्यों की नियुक्ति की, पूर्ववर्ती सदस्यों द्वारा केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को संशोधित करने की शक्तियों का प्रयोग किया क्योंकि नियुक्ति का आदेश केंद्र सरकार द्वारा पहले से ही गठित अधिकरण के पुनर्गठन के समान था। उस अवधि के दौरान जब केवल एक सदस्य था और अधिकरण में तीन सदस्यों की कानूनन आवश्यकता थी, अधिकरण द्वारा अपीलकर्ता के विचारण को जारी रखने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। अधिकरण द्वारा दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति जिनमें एक अध्यक्ष भी था, के पश्चात् ही विचारण प्रारम्भ किया। इसके बाद जब अधिकरण के एक सदस्य के द्वारा ही कार्य शुरू किया गया, तब तक 1950 के पंजाब अधिनियम x द्वारा कानून में पहले ही संशोधन कर दिया गया, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि अधिकरण में तीन सदस्यों के स्थान पर केवल एक सदस्य शामिल होगा। इस प्रकार अधिकरण का गठन व संचालन प्रत्येक चरण में उचित था। {221जी-222 सी}

(viii) साक्ष्य में इस्तेमाल की गई युद्ध डायरीयां आधिकारिक कृत्यों के रिकॉर्ड थे और वास्तव में गवाहों के विशिष्ट साक्ष्य थे, उन्हें संधारित करने वाली सेना की इकाइयों द्वारा सुरक्षित बनाये रखने नियमानुसार

आवश्यक था। इस प्रकार संधारित डायरियां साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत आधिकारिक कृत्यों के रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार्य थीं और उन्हें साक्ष्य में ग्राह्य किया जाना त्रुटिग्रस्त नहीं था।

युद्ध डायरियों को धारा 342 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार अपराधी के परीक्षण के दौरान उसके सामने रखा जाना आवश्यक नहीं था, क्योंकि उक्त धारा के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली परिस्थितियों को अभियुक्त के सामने रखा जाना अपेक्षित था, न कि उन परिस्थितियों के प्रमाण में साक्ष्य के प्रत्येक हिस्से को अभियुक्त के सामने रखना। {224 एफ, 225 सी-ई}

फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार फौजदारी अपील संख्यांक 150 और 151, 1962 का 196 से 199।

फौजदारी अपील संख्या 478 और 479 में पंजाब उच्च न्यायालय के 21 मार्च, 1962 के फैसले और आदेश के विरुद्ध अपील और 1949 के क्रमशः 41, 176, 478 और 479।

हीरा लाल सिब्बल, जे.सी. तलवार और आरएल कोहली, अपीलकर्ता के लिए (फौजदारी अपील संख्यांक 1962 का 150 और 151) और प्रतिवादी (फौजदारी अपील संख्यांक 1962 के 196 से 199)।

पुरषोत्तम त्रिकुमदास, के.सी. चावला, और आरएन संचेती, प्रतिवादी के लिए (फौजदारी अपील संख्यांक 1962 का 150 और 151) और अपीलकर्ता के (फौजदारी अपील संख्यांक 1962 के 196 से 199)।

न्यायाधिपति भार्गव, जे. द्वारा न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

ये छह अपीलें, पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्रों के आधार पर दायर की गईं, जो कि उस न्यायालय के एक ही फैसले से उत्पन्न हुई हैं, और परिणामस्वरूप उन्हें एक साथ सुना गया है। 1962 की दो अपील संख्या 150 और 151 बखशीश सिंह धालीवाल (इसके बाद अपीलकर्ता के रूप में संदर्भित) द्वारा धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के तहत छल के तीन अलग-अलग आरोपों पर उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट सजा के विरुद्ध दायर की गई हैं। 1962 की शेष चार अपील संख्या 196 से 199 पंजाब राज्य ने उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध छल के अपराध के संबंध में दर्ज किये गये कुछ रिकॉर्ड के आधार पर दोषमुक्ति के विरुद्ध दायर की।

मूल रूप से 1943 के अध्यादेश 29 के तहत गठित एक विशेष अधिकरण के समक्ष कुल मिलाकर चार विचारण थे। इन चार विचारण में, अपीलकर्ता पर बर्मा सरकार को मिथ्या अभ्यावेदन देकर और उस कार्य के लिये, जो अपीलार्थी द्वारा ठेकेदार के रूप में किया ही नहीं गया था, उक्त

कार्य किया जाना दिखाकर और उसके बदले भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होना बताकर 6 लाख रुपये से अधिक की सीमा के धन का भुगतान प्राप्त करके छल के दस अलग-अलग अपराध करने का आरोप लगाया गया था।

इन अपीलों के निर्णय के लिए जो तथ्य प्रासंगिक हैं, वे बहुत ही संक्षिप्त दायरे में आते हैं। वर्ष 1942 में जापानी आक्रमण के परिणामस्वरूप बर्मा सरकार और वहां कार्यरत मित्र सेनाओं को बर्मा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। बर्मा से निष्कासन और उस देश की रक्षा के प्रयोजनों के लिए, बर्मा सरकार और सेना को सड़कों के निर्माण, पुलों की मरम्मत और निर्माण, पुरानी पटरियों को मजबूत करने और मरम्मत करने और रेलवे लाइनों को मोटर सड़कों में परिवर्तित करने की प्रकृति के कुछ कार्यों को निष्पादित करना पड़ा। इनमें से कुछ कार्यों को सेना ने स्वयं निष्पादित किया, जबकि अन्य को ठेकेदारों को सौंपा गया।

निष्कासन के बाद, बर्मा सरकार शिमला में स्थित थी। अशांत परिस्थितियों के कारण, विभिन्न ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों का कोई सटीक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था और परिणामस्वरूप, अगस्त 1942 में, बर्मा सरकार ने उन ठेकेदारों से दावे आमंत्रित करने के लिए एक विज्ञापन जारी किया, जिन्होंने इस अवधि दौरान बर्मा में काम निष्पादित किया था या सामग्री की आपूर्ति की थी और अभी तक भुगतान नहीं किया गया था।

अपीलकर्ता ने विभिन्न कार्यों के संबंध में कई दावे प्रस्तुत किए, जिनके बारे में उनका दावा था कि उन्हें उनके द्वारा निष्पादित किया गया था और साथ ही सामग्रियों की आपूर्ति की थी। ये दावे बिलों के रूप में थे और उन कार्यों के संबंध में थे जिनके बारे में उनका दावा था कि ये सेना की विभिन्न इकाइयों के निर्देशों के तहत किए गए थे। ये बिल तीन अलग-अलग अधिकारियों, हैंडरसन, नास्से और करम सिंह को सत्यापन के लिए भेजे गए थे, और उनके सत्यापन के बाद, उन बिलों के संबंध में अपीलकर्ता को भुगतान किया एक या दो मामलों में, भुगतान केवल आंशिक थे, जबकि अन्य मामलों में उन अधिकारियों द्वारा अनुशंसित सभी दावों का भुगतान कर दिया गया था।

अपीलकर्ता के मामले में, यह पाया गया कि उसने कथित तौर पर किए गए विभिन्न कार्यों या आपूर्ति की गई सामग्रियों के लिए 20 दावे किए थे। इनमें से सोलह दावे कुल मिलाकर रु. 16,31,808/- जिसमें से रु. 6,87,173/- का भुगतान कोहलापुर स्थित वर्मा सरकार के साथ कार्यरत सैन्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा जारी चेक के माध्यम से किया गया था।

इसके बाद, अपीलकर्ता द्वारा किए गए दावों सहित विभिन्न ठेकेदारों द्वारा किए गए कई दावों के संबंध में बर्मा सरकार का संदेह उत्पन्न हुआ, और यह पता चला कि कुछ दावे मिथ्या और फर्जी थे। परिणामस्वरूप

आगे की जांच की गई और उसके बाद अपीलकर्ता पर दस अलग-अलग आरोपों के संबंध में अभियोजन चलाया गया। चूंकि ऐसे कई मामलों की सुनवाई होनी थी, 1943 का अध्यादेश संख्या 29 जारी करके विशेष अधिकरण का गठन किया गया था, और इनमें से दो अधिकरण लाहौर में स्थित थे। अपीलकर्ता के खिलाफ मामले इन अधिकरणों में एक को सौंपे गए थे।

अधिकरण के समक्ष, अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपित दस अपराधों को प्रकरण संख्या 21 से 26 और 31 में 34 दिए गए थे। हालाँकि, इनमें से कुछ मामलों की एक साथ कोशिश की गई और परिणाम यह हुआ कि अंततः, चार मुकदमे हुए जिनमें अपीलकर्ता पर इन दस आरोपों के अभियोग चलाये गये। विशेष अधिकरण ने अपीलकर्ता को सभी आरोपों के संबंध में दोषी ठहराया लेकिन अपील पर, उच्च न्यायालय ने केवल तीन आरोपों के संबंध में दोषसिद्धि को बरकरार रखा। ये आरोप आरोप संख्या 21, आरोप संख्या 22 और आरोप संख्या 26 का हिस्सा थे। अन्य आरोपों के संबंध में, उच्च न्यायालय ने एक निष्कर्ष अभिलिखित किया कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा कि जो दावे अपीलकर्ता द्वारा किये गये ये सभी फर्जी थे और उनके द्वारा नहीं किए गए कार्यों या उनके द्वारा आपूर्ति नहीं की गई सामग्री के संबंध में थे इसलिए अपीलकर्ता को संदेह का लाभ दिया गया और वे दोषमुक्त कर दिया गया।

अपीलकर्ता पर विशेष अधिकरण द्वारा एक ही मुकदमे में आरोप संख्या 21, 22 और 23 के लिए मुकदमा चलाया गया था, जबकि आरोप संख्या 26 एक अलग मुकदमे की विषय-वस्तु थी। आरोप संख्या 21, आरोप संख्या 22 और आरोप संख्या 26 के भाग के संबंध में उनकी दोषसिद्धि को उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है, अपीलकर्ता ने इस प्रकार इस न्यायालय में दो अपील संख्या 150 और 151/1962 दायर की है। उन्हें आरोप संख्या 21 और आरोप संख्या 23 के भाग से दोषमुक्त कर दिया गया था, जिनकी सुनवाई एक मुकदमे में आरोप संख्या 22 के साथ की गई थी, और इसी तरह उन्हें अन्य तीन मुकदमों में भी अन्य आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है। हमारे समक्ष चार राज्य अपीले उन आरोपों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने के इन आदेशों के खिलाफ है जो चार अलग-अलग विचारण की विषय-वस्तु थी।

अपीलकर्ता द्वारा दायर दो अपीलों में उनकी ओर से कानून के कई बिंदुओं पर हमारे सामने तर्क दिया गया है। पहला बिंदु जिस पर बहुत जोर डाला गया था वह यह था कि अपीलकर्ता पर दस अलग-अलग आरोपों के संबंध में चार अलग-अलग मामलों में अभियोग चलाकर गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित किया गया था, जबकि वास्तव में उसने जो कुछ किया वह एक साथ बिलों का एक सेट जमा करना था और दस अलग-अलग मिथ्या अभ्यावेदन नहीं दिये गये थे जो बर्मा सरकार को उसे भुगतान करने के

लिए प्रेरित कर सकती थी। हमारा ध्यान इस तर्क का समर्थन करने के लिए कि अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए सभी दावे इस पत्र के साथ एक साथ प्रस्तुत किए गए थे, और परिणामस्वरूप एक एकल प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाना चाहिए, पत्र Ext. DR दिनांक 3 नवंबर, 1942, की ओर आकर्षित किया गया।

हालाँकि, राज्य की ओर से हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया था कि इस पत्र में 'दावे शब्द से पहले के संख्या 02 को मिटा दिया गया था, इसलिए यह पत्र वास्तव में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए 20 दावों में से केवल 02 को संदर्भित करता है और इस तर्क के समर्थन में पत्र Ext. DS प्रस्तुत किया जिनमें सरकार ने पत्र Ext. DR का हवाला देते हुए केवल 2 दावों की प्राप्ति स्वीकार की। राज्य का मामला यह था कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत 20 दावों वाले विभिन्न बिलों को एक अभ्यावेदन नहीं माना जा सकता था।

ऐसा प्रतीत होता है कि भले ही यह तथ्य हो कि ये सभी दावे अपीलकर्ता द्वारा केवल एक ही कवरिंग लेटर के साथ प्रस्तुत किए गए थे, यह नहीं माना जा सकता कि वे एक ही मिथ्या अभ्यावेदन के बराबर थे। दावे कई कार्यों या सामग्रियों की आपूर्ति से संबंधित हैं जिन्हें अपीलकर्ता ने दावा किया है कि उन्होंने इसे पूरा किया है। प्रत्येक भिन्न कार्य या सामग्रियों की अलग-अलग आपूर्ति किए गए, किसी अन्य कार्य या की गई

आपूर्ति से संबंधित एक अलग और विशिष्ट अभ्यावेदन होगा। इस प्रकार, एक मुकदमे में जिसमें आरोप 21, 22 और 23 शामिल थे, अधिकरण द्वारा तीन अलग-अलग आरोप तय किए गए थे। पहला आरोप ताउंगडविग्यी और क्याउकपाडाउंग के बीच रेलवे टे^aक के रूपांतरण के साथ-साथ उन स्थानों पर सामग्री की आपूर्ति से संबंधित है। दूसरा आरोप, जो आरोप संख्या 22 से संबंधित था, उस कार्य के संबंध में था जिसके बारे में दावा किया गया था कि यह म्योथिट से उत्तर की ओर एक ट्रेक के सुधार के संबंध में किया गया था, जो कि क्याउकापदाउंग और मिकटीला के बीच मुख्य ट्रंक रोड के साथ उसके जंक्शन तक था, जबकि तीसरा आरोप जिसकी आरोप संख्या 23 थी उन सामग्रियों के संबंध में था जिनके बारे में दावा किया गया था कि उन्हें एलानम्यों में आपूर्ति की गई थी। इस प्रकार लगाए गए तीन आरोप तीन अलग-अलग स्थानों पर किये गये कार्यों या आपूर्ति से संबंधित थे जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र था। इनमें से प्रत्येक आरोप के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा दावे प्रस्तुत किए गए थे और वे दावे उसके द्वारा किए गए अभ्यावेदन के बराबर थे कि उसने उन कार्यों को किया था या उन आपूर्तियों को किया था। परिणामस्वरूप यह मानने में कोई त्रुटि नहीं हुई कि इस मुकदमे में अपीलकर्ता पर एक ही तरह के तीन अलग-अलग अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा था, इसलिए मामलों को दस अलग-अलग आरोपों में विभाजित करना पूरी तरह से उचित था।

इन परिस्थितियों में, अपीलकर्ता की ओर से श्री आर.एल. आनंद ने हमारे सामने उस मामले को वैधता को चुनौती दी, जिसमें अपीलकर्ता पर आरोप 21, 22 और 23 के लिए अलग आधार पर मुकदमा चलाया गया था, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष पहले नहीं रखा गया था। उन्होंने आग्रह किया कि अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए दावे की जांच जिसके आधार पर आरोप 21 और 23 उठाए गए थे, यह दिखाएगा कि वास्तव में अपीलकर्ता द्वारा तीन अलग-अलग दावे थे, और चूंकि इन पर आरोप संख्या 22 के साथ मुकदमा चलाया गया था, जिसमें एक अलग दावा था, अभियोग एक ही तरह के चार आरोपों के संबंध में होने के कारण दूषित हो गया था, क्योंकि यह कानून में स्वीकार्य नहीं है। तर्क विफल हो जाता है, क्योंकि दावे से ही यह स्पष्ट है कि आरोप संख्या 21 वास्तव में एक एकल आरोप था, न कि दो आरोप। यह अपीलकर्ता द्वारा उसी स्थान पर किए गए कार्य और आपूर्ति की गई सामग्री के लिए किए गए दावे पर आधारित था, जैसे ताउंगडविग्यी और क्याउकपाडाउंग। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि अपीलकर्ता द्वारा एक ही स्थान पर किए गए कार्य और आपूर्ति की गई सामग्री के संबंध में अपने दावे में किया गया प्रतिनिधित्व, एक ही प्रतिनिधित्व के बराबर था, इसलिए, वास्तव में, इस परीक्षण में अपीलकर्ता फर्जी कार्यों या आपूर्ति की तीन वस्तुओं से संबंधित तीन झूठे अभ्यावेदन के आधार पर केवल तीन आरोपों के संबंध में मुकदमा चलाया गया था।

इसलिए, अपीलकर्ता के खिलाफ कोई भी मुकदमा आरोपों के कुसंयोजन या आरोपों के पृथक्करण से संबंधित किसी भी त्रुटि के कारण दूषित नहीं हुआ।

कानून का अगला प्रश्न यह उठाया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा पाए गए तथ्यों पर भी, अपीलकर्ता को गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था क्योंकि उसके विरुद्ध छल का कोई अपराध नहीं बनाया गया था। यह तर्क इस परिस्थिति पर आधारित था कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे, जो फर्जी पाए गए थे, उन्हें विभिन्न अधिकारियों के पास सत्यापन के लिए भेजा गया था और उन अधिकारियों द्वारा अपीलकर्ता के दावों की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर भुगतान स्वीकृत किया गया था और अपीलकर्ता को भुगतान किया गया था। दलील यह थी कि भुगतान अपीलकर्ता द्वारा किए गए किसी अभ्यावेदन का परिणाम नहीं था, बल्कि उन अधिकारियों की रिपोर्ट में शामिल गलत प्रस्तुतिकरण का परिणाम था, इसलिए यदि छल का कोई अपराध हुआ था, तो यह उन अधिकारियों द्वारा किया गया था, न कि अपीलकर्ता द्वारा।

इस तर्क में भ्रंति बिल्कुल स्पष्ट है। यह सही है कि भुगतान बर्मा सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था और अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावों पर उनके अपने अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही किया गया था, लेकिन भुगतान आखिरकार केवल इसलिए किया गया क्योंकि सर्वप्रथम

अपीलकर्ता ने वे दावे प्रस्तुत किए थे। अपीलकर्ता द्वारा बिलों में शामिल लिखित दावों में किए गए अभ्यावेदन बाद की सभी कार्यवाहियों का आधार थे, जिसके परिणामस्वरूप उसे भुगतान किया गया। इन अभ्यावेदनों में फर्जी दावे थे और भुगतान के आदेश उन्हीं दावों पर आधारित थे। जिन अधिकारियों ने दावों को गलत तरीके से सत्यापित किया, उन्हें निश्चित रूप से अपीलकर्ता को उसके झूठे अभ्यावेदन का समर्थन करने के लिए दुष्प्रेरण का दोषी ठहराया जा सकता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता को किए गए भुगतान अपीलकर्ता द्वारा स्वयं किए गए अभ्यावेदन से जुड़े या परेरित नहीं थे। वास्तव में, मुख्य रूप से, यह अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल उसके अभ्यावेदन थे जिनकी परिणति अंततः बर्मा सरकार द्वारा अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए दावों को पूरा करने के लिए धन देने के रूप में हुई। माता प्रसाद बनाम एम्परर (1) के मामले में जिस फैसले की सत्यता पर अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने भरोसा किया था, उस पर हमें रोक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस मामले में तथ्य अलग थे और माता प्रसाद को दोषसिद्ध नहीं पाया गया क्योंकि उन्होंने स्वयं कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया था। यह सब शिकायतकर्ता द्वारा धन के भुगतान के लिए प्रेरित किया गया था, और निष्कर्ष यह था कि धन की अग्रिम राशि पूरी तरह से हीरालाल द्वारा की गई प्रवंचना से प्रेरित थी। इन

परिस्थितियों में यह निष्कर्ष पूरी तरह से उचित था कि अपीलकर्ता छल का दोषी था।

इस संबंध में, एक और बिन्दु यह रखा गया कि अपीलकर्ता को धारा 420 भारतीय दंड संहिता के स्थान पर धारा 417 आई.पी.सी. के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए था, क्योंकि, जैसे ही मिथ्या दावों के संबंध में भुगतान को मंजूरी देने के लिखित आदेश दिए गए, धारा 417 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध पूर्ण हो गया और बाद में किए गए भुगतानों को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए था। इस तर्क को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि बिलों को मंजूरी देने वाले आदेशों के बाद के भुगतान, उसी लेनदेन का हिस्सा थे जो अपीलकर्ता द्वारा किए गए झूठे अभ्यावेदन के साथ शुरू हुआ था जो भुगतान किए जाने के बाद ही संपन्न हुआ और केवल उन कार्यवाहियों में मंजूरी के आदेश पारित होने पर समाप्त नहीं हुआ था। वास्तव में, हर मामले में जहां छल करने वाले व्यक्ति द्वारा संपत्ति हस्तांतरित की जाती है, वहां हमेशा एक चरण ऐसा होना चाहिए जब व्यक्ति अपने द्वारा किए गए झूठे अभ्यावेदन को स्वीकार करने पर संपत्ति देने का मन बना लेता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे मामलों में अपराध करने वाले व्यक्ति पर केवल आईपीसी की धारा 417 के तहत छल के साधारण अपराध के लिए अभियोग चलाया जा सकता है, और धारा 420 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है क्योंकि व्यक्ति ने ऐसा

करने का निर्णय लेने के बाद उसकी संपत्ति के साथ छल किया है। धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता की सजा इन परिस्थितियों में किसी भी तरह से दूषित नहीं है।

छल के अपराध के लिए दोषसिद्धि के लिए अपीलकर्ता के दायित्व को एक अन्य आधार पर चुनौती दी गई थी। यह आग्रह किया गया कि अपीलकर्ता ने 5 अप्रैल, 1942 को बर्मा छोड़ दिया, जबकि जो दावे फर्जी पाए गए थे, वे काफी हद तक उस तारीख के बाद किए गए कार्यों या कथित तौर पर आपूर्ति की गई सामग्रियों से संबंधित थे, ताकि अपीलकर्ता को कोई व्यक्तिगत जानकारी न हो सके कि उसके द्वारा लगाए गए दावे फर्जी थे। जिन आरोपों के लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया है. उनके संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि जिन कार्यों से संबंधित दावे किए गए थे, वे बिल्कुल भी नहीं किए गए थे, या संबंधित आपूर्ति कभी नहीं की गई थी। एक बार निष्कर्ष इस तरीके से स्पष्ट रूप से दर्ज हो जाने के बाद, हमें नहीं लगता कि अभियोजन पक्ष पर यह स्थापित करने के लिए कोई भार डाला गया था कि अपीलकर्ता को अपने दावों की फर्जी प्रकृति के बारे में व्यक्तिगत जानकारी थी। ज्ञान में अपीलकर्ता की मनःस्थिति शामिल होती है और अभियोजन पक्ष द्वारा संभवतः उस ज्ञान का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिया जा सकता है। तथ्य यह है कि दावे फर्जी थे और सच्चे तथ्यों के अनुरूप नहीं थे, निष्कर्षतः

अपीलकर्ता जानता था कि इन दावों में वह जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वह झूठा था। यह महत्वपूर्ण है कि अपीलकर्ता किसी भी स्पष्टीकरण के साथ आगे नहीं आया है कि उसने ये दावे किसी विशेष व्यक्ति द्वारा उसे दी गई जानकारी के आधार पर किए हैं, जिसकी बात पर उसके पास संदेह करने का कोई कारण नहीं था। वास्तव में, दावे उन तथ्यों पर आधारित बताए गए हैं कि अपीलकर्ता जानता था कि वह दावों में शामिल राशि का हकदार था क्योंकि उसने काम किया था या दावों से संबंधित सामग्री की आपूर्ति की थी।

अगला बिन्दु यह था कि इस मामले में अपीलकर्ता का मुकदमा दूषित हो गया था, क्योंकि एक निश्चित चरण तक उस पर हैंडरसन के साथ विचारण चलाया गया था, जिस पर धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता सपठित धारा 109 भारतीय दण्ड संहिता के तहत छल के लिए दुष्प्रेरण के अपराध का आरोप लगाया गया था और हैंडरसन के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के प्रावधानानुसार केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना विचारण चलाया गया।

इस तर्क में आधार नहीं होने के मुख्यतः दो कारण हैं। सबसे पहला यह कि इस न्यायालय द्वारा के. सतवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य के समान मामले में पहले ही यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि छल के लिए दुष्प्रेरण के अपराध के लिए हैंडरसन के वैध मुकदमे के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की

धारा 197 की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह नहीं माना जा सकता है कि ऐसा अपराध करने वाला कोई लोक सेवक अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है। इस संबंध में, विद्वान वकील ने हमें सुनील कुमार पॉल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में इस न्यायालय के बाद के फैसले का हवाला दिया, जहां इस न्यायालय ने एक सरकारी कर्मचारी के मामले में, जिसने गलत बिल जमा किया था, कहा था कि मिथ्या प्रस्तुतिकरण का कार्य जिसके परिणामस्वरूप छल का अपराध सम्पन्न हुआ, उस सरकारी सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के दौरान किया गया था। हालाँकि, उस मामले के तथ्य अलग थे, क्योंकि उस मामले में यह माना गया था कि सरकारी कर्मचारी द्वारा बिल जमा करवाना ही वह कार्य था जिसके लिए उस पर मुकदमा चलाया जाना था. और वह कार्य उसके द्वारा किया गया माना गया था वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया था। हस्तगत मामले में, साथ ही इससे पहले सतवंत सिंह के मामले में, हैंडरसन पर उन बिलों की सत्यता के प्रमाणीकरण के कार्य के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा रहा था जो उसे सत्यापन के लिए भेजे गए थे, बल्कि उस पर मुकदमा इसलिये चलाया जाना था कि उसने उन व्यक्तियों द्वारा किए गए छल के अपराध को बढ़ावा दिया जिन्होंने उन बिलों की सत्यता को गलत तरीके से प्रमाणित करके बिल जमा किए थे। इस प्रकार मुख्य अपराधियों को दुष्प्रेरण का

कृत्य संभवतः एक लोक सेवक के रूप में लोक कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया, नहीं माना जा सकता है।

दूसरा कारण यह है कि अपीलकर्ता के विरुद्ध विचारण कुछ हद तक आगे बढ़ने के बाद, हैंडरसन के विरुद्ध विधारण अलग कर दिया गया और केवल अपीलकर्ता पर चारों मामलों में विचारण चलाया गया। अपीलकर्ता एक सरकारी कर्मचारी नहीं था, बल्कि केवल एक स्वतंत्र ठेकेदार था. और उसके मामले में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त करने का कोई सवाल ही नहीं था। इसलिए, हैंडरसन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी के अभाव में उनके मुकदमे अप्रभावित रहेंगे।

इस संबंध में यह भी आग्रह किया गया कि हैंडरसन के मामले को अपीलकर्ता के मामले से अलग करने के बाद नए सिरे से सुनवाई होनी चाहिए थी। हालाँकि, इस तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई कारण नहीं दिया जा सका। जहां तक अपीलकर्ता का सवाल है. पूरी सुनवाई तब हुई जब वह मौजूद था और उसके खिलाफ मामला इस तथ्य से अप्रभावित रहा कि सुनवाई के दौरान हैंडरसन पर भी कथित अपराध को बढ़ावा देने के लिए उसके साथ मुकदमा चलाया जा रहा था, जबकि मुकदमे के शेष भाग के दौरान, उस पर उस अपराध के लिए अकेले मुकदमा चलाया जा रहा था जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया था। इसके

अलावा ऐसी परिस्थितियाँ भी हैं कि अपीलकर्ता द्वारा किसी भी स्तर पर नए सिरे से सुनवाई के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया था. और यहाँ तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में भी. इस संबंध में कोई शिकायत सामने नहीं रखी गई थी।

हमारे सामने मुकदमों की वैधता को भी इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि जिस विशेष अधिकरण ने अपीलकर्ता को दोषसिद्ध किया था, वह कानून के अनुसार गठित नहीं किया गया था और विचारण करने में अक्षम था। हमारे समक्ष मुख्य दलील, जो उस पहलू से अलग थी जिसमें उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया गया था, इस तथ्य पर आधारित थी कि विशेष अधिकरण का गठन 1943 के अध्यादेश संख्या 29 के तहत किया गया था जो कि धारा 102 भारत सरकार, अधिनियम, 1935, के तहत जारी नहीं किया गया था लेकिन उस अधिनियम की नोवी अनुसूची के धारा 72 के तहत किया गया। यह आग्रह किया गया कि भारत सरकार अधिनियम की धारा 72 में ही उल्लेखित है कि उस प्रावधान के तहत जारी किया गया अध्यादेश इसके प्रख्यापन से छह महीने से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगा। इस आधार पर विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि 1944 और 1945 में इस अध्यादेश और साथ ही 1946 का पंजाब अध्यादेश iii में संशोधन कर अध्यादेश जारी किए गए जिन्होंने विशेष अधिकरण को निरन्तर जीवनकाल को अप्रभावी कर दिया है क्योंकि उनका

उद्देश्य उन अधिकरण के अस्तित्व को जारी रखना था जो 9 सितंबर, 1943, अध्यादेश संख्या 29/1943 के प्रख्यापन की दिनांक से छह महीने की समाप्ति पर पहले ही निष्क्रिय हो गया था। यह तर्क स्पष्ट रूप से भारत और बर्मा (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम, 1940 (3 और 4 जियो. 6, अध्याय 33) की धारा का 1(3) के प्रभाव को नजरअंदाज करते हुए गलतफहमी के तहत किया गया था जिसने भारत सरकार अधिनियम, 1935 की नौवीं अनुसूची के 72 धारा के संचालन को निलंबित कर दिया जिसके तहत अध्यादेश का जीवन इसके प्रख्यापन से छह महीने तक सीमित था। दरअसल, यह बिन्दु जे के गैस प्लांट मैनुफैक्चरिंग कंपनी (रामपुर) लिमिटेड और अन्य बनाम द किंग एम्परर के मामले में फेडरल कोर्ट के सामने आया था, जहां संघीय न्यायालय ने माना कि यह अध्यादेश 29/1943 भारत और बर्मा (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम, 1940 की धारा 1(3) के प्रावधानों के मद्देनजर 30 सितंबर, 1946 को समाप्त हो गया, इसलिए 30-9-1946 तक, उस अध्यादेश के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित अधिकरण सक्षम रूप से कार्य कर रहा था।

1946 का पंजाब अध्यादेश iii जो अक्टूबर, 1946 को लागू हुआ, उसके समक्ष लंबित मामलों की सुनवाई के उद्देश्य से उस अधिकरण की शक्तियों को जारी रखता है, ताकि कोई अंतराल न हो और अधिकरण पहले से ही 1943 के अध्यादेश 29 के तहत काम कर रहा हो, 1946 के पंजाब

अध्यादेश iii के प्रावधानों के अनुसार वैध रूप से कार्य करना जारी रखे। इस अध्यादेश को बाद में 1950 के पंजाब अधिनियम x द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिससे अधिकरण का जीवनकाल और उसकी शक्तियां जारी रही, यद्यपि अधिकरण की सदस्यता तीन से घटाकर एक कर दी गयी। इसीलिए विशेष अधिकरण, जिसने अपीलकर्ता के विरुद्ध मामलों की सुनवाई की, बिना किसी रुकावट के विभिन्न अध्यादेशों और पंजाब अधिनियम के अनुसार वैध रूप से बिना किसी बाधा के कार्य किया।

वैकल्पिक रूप से, अपीलकर्ता को दोषसिद्ध करने वाले अधिकरण के गठन को एक अन्य आधार पर चुनौती दी गई थी, अर्थात्, एक चरण में, अधिकरण की सदस्यता जिसने कानून के तहत तीन सदस्यों को शामिल करना आवश्यक था, जिसे घटाकर केवल एक सदस्य कर दिया गया और बाद में अन्य दो सदस्यों की नियुक्ति पंजाब सरकार द्वारा की गई, जिसके पास ऐसी नियुक्ति करने का कोई अधिकार या शक्ति निहित नहीं थी। 1943 के अध्यादेश संख्या 29 के तहत, विशेष अधिकरण के गठन की शक्ति केंद्र सरकार में निहित थी. और केंद्र सरकार ने वास्तव में तीन सदस्यों वाला एक अधिकरण गठित किया। वह अधिकरण 30 सितंबर 1946 तक जारी रहा और उसके बाद, इसने 1946 के पंजाब अध्यादेश iii के प्रावधानों के आधार पर कार्य किया। ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में वर्ष 1947 में किसी समय, सदस्यों में से एक की मृत्यु हो गई और अधिकरण के अध्यक्ष ने

उनका भारत से प्रस्थान के बाद कार्य करना बंद कर दिया। इसके बाद, पंजाब सरकार द्वारा अधिकरण में दो नए सदस्यों को नियुक्त किया गया और उनमें से एक को अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया। अपीलकता की ओर से आग्रह किया गया कि 1946 के पंजाब अध्यादेश iii के तहत, पंजाब सरकार ने अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति हासिल कर ली, लेकिन उस अध्यादेश ने पंजाब सरकार को अधिकरण के पुनर्गठन या सदस्यों की नियुक्ति की शक्ति प्रदान नहीं की। उक्त आग्रह पंजाब अध्यादेश की धारा 3(2) के प्रावधानों पर आधारित था, जिसमें उल्लेखित था कि 1943 के अध्यादेश के प्रावधान लागू रहेंगे और अधिकरण के संबंध में लागू होंगे, सिवाय धारा 1 की उपधारा (2), धारा 5 (1) जे. जो कि केन्द्र सरकार की धारा 3 (बी), धारा 4 (3) और धारा 11 संशोधन की शक्तियों के आधीन रहते हुए पंजाब अध्यादेश के प्रारंभ से, प्रांतीय सरकार की शक्तियाँ थी। अधिकरण के गठन की शक्ति 1943 के अध्यादेश के धारा 3 के मुख्य खंड में निहित थी और इस प्रमुख खंड का कोई उल्लेख नहीं था, जहां संशोधन द्वारा, केंद्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग पंजाब सरकार द्वारा पंजाब अध्यादेश की धारा 3(2) के तहत किया जाना था।

यद्यपि यह तर्क पंजाब अध्यादेश की धारा 3 के प्रभाव को नजरअंदाज करता है, जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा 1943 के अध्यादेश

की धारा 3, धारा 4 की उपधारा (3) और धारा 11 के तहत जारी की गई सभी अधिसूचनाएं और बनाए गए सभी नियम, जहां तक वे अधिकरणों पर लागू होते थे, पंजाब अध्यादेश के तहत पंजाब सरकार द्वारा अधिक्रमण या संशोधित होने तक लागू रहेंगे। इस प्रकार, इस प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पंजाब सरकार के पास धारा 3, धारा 4 की उपधारा (3) और धारा 11 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं और बनाए गए नियमों को अधिलंघित करने या संशोधित करने की शक्ति है। परिणामतः केंद्र सरकार द्वारा 1943 के अध्यादेश के धारा 3 के तहत विशेष अधिकरण के गठन के लिए जारी की गई अधिसूचनाओं को पंजाब सरकार द्वारा अधिलंघित या संशोधित किया जा सकता है। जब पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दो मूल सदस्यों के स्थान पर दो सदस्यों की नियुक्ति की, तो पूर्ववर्ती सदस्यों द्वारा केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को संशोधित करने की शक्तियों का प्रयोग किया क्योंकि नियुक्ति का आदेश केंद्र सरकार द्वारा पहले से ही गठित अधिकरण के पुनर्गठन के समान था।

इसलिए, पंजाब सरकार का आदेश पंजाब अध्यादेश की धारा 3 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के दायरे में पारित किया गया था। उस अवधि के दौरान जब केवल एक सदस्य था और अधिकरण में तीन सदस्यों की कानूनन आवश्यकता थी, अधिकरण द्वारा अपीलकर्ता के विचारण को जारी रखने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। अधिकरण द्वारा दो अन्य सदस्यों की

नियुक्ति जिनमें एक अध्यक्ष भी था, के पश्चात् ही विचारण प्रारम्भ किया। इसके बाद जब अधिकरण के एक सदस्य के द्वारा ही कार्य शुरू किया गया, तब तक 1950 के पंजाब अधिनियम x द्वारा कानून में पहले ही संशोधन कर दिया गया, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि अधिकरण में तीन सदस्यों के स्थान पर केवल एक सदस्य शामिल होगा। इस प्रकार अधिकरण का गठन व संचालन प्रत्येक चरण में उचित था।

अपीलकर्ता की ओर से आग्रह किया गया अगला बिंदु यह था कि इन विचारणों में, अपीलकर्ता को अपने बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था, और यह अपीलकर्ता की कोई गलती के बिना हुआ था। इस संबंध में उन गवाहों का संदर्भ दिया गया जो तीन अलग-अलग देशों में थे। कुछ गवाह पाकिस्तान में थे कुछ इंग्लैंड में और कुछ बर्मा में। जहां तक पाकिस्तान में गवाहों का सवाल है, अधिकरण ने 6 अप्रैल 1949 को एक आदेश दर्ज किया, जिसमें उन गवाहों का परीक्षण करने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि भारत की अदालतों द्वारा जारी किए गए समन को पाकिस्तान सरकार वहां रहने वाले व्यक्तियों पर समन की सेवा को प्रभावित करने के लिए भी तैयार नहीं थी। यह महत्वपूर्ण है कि अधिकरण के इस आदेश के बाद, मामला पंजाब उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष आया और उस स्तर पर पाकिस्तान के इन गवाहों से पूछताछ न किए जाने के बारे में कोई शिकायत नहीं की गई, भले ही

इस संबंध में इंग्लैंड और बर्मा में गवाहों के समय में एक शिकायत सामने रखी गई थी। खंडपीठ ने 25 सितंबर, 1951 को मामले की सुनवाई की और इंग्लैंड और बर्मा में गवाहों के परीक्षण के लिए अपीलकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। अब अपीलकर्ता के लिए इस अदालत में नई शिकायत करने के लिए बहुत देर हो चुकी है कि पाकिस्तान में गवाहों में पूछताछ नहीं की गई।

इंग्लैंड और बर्मा में गवाहों के संबंध में, वास्तव में उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा एक आदेश दिया गया था जिसमें अधिकरण को उनकी परीक्षा के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया था इस संबंध में कदम उठाए गए और अपीलकर्ता के आप पर इंग्लैंड में तीन गवाहों से कमीशन पर पूछताछ की गई। अन्य को उपलब्ध न होने के कारण छोड़ दिया गया। इसलिए, इंग्लैंड में गवाहों के परीक्षण करने में कोई विफलता नहीं हुई है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस बिन्दू पर हमारे सामने जोर देकर कहा कि अपीलकर्ता के प्रति वास्तविक पूर्वाग्रह बर्मा में मौजूद गवाहों से पूछताछ के अभाव के कारण हुआ। अधिकरण द्वारा एक बरण में उनकी परीक्षा से इनकार कर दिया गया था और उस इनकार के खिलाफ अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख किया। जैसा कि हमने पहले कहा है. 25 सितंबर, 1951 को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने उनके परीक्षण के लिए अधिकरण द्वारा कदम उठाने का निर्देश दिया। इसके बाद,

कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई और समय-समय पर अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और वर्ष 1954 तक विभिन्न आदेश दिए गए। वर्ष 1954 में बर्मा में दो स्थानों के जिला मजिस्ट्रेटों को वास्तव में गवाहों के परीक्षण के लिए आयोग जारी किए गए थे, जो कि पार्टियों की आम सहमति से उन व्यक्तियों के रूप में चुना जाता है जिनके सामने उन गवाहों की आसानी से परीक्षण जा सकती है। अपीलकर्ता को बर्मा जाने के लिए और अपनी उपस्थिति में कमीशन निष्पादित करने के लिए 3000/- रुपये की राशि दी गई थी। शिकायत यह है कि यह राशि वास्तव में कभी भुगतान नहीं की गई और इसके अलावा, किसी भी मामले में, अपीलकर्ता को पर्याप्त धनराशि परदान नहीं की गई ताकि वह हवाई मार्ग से समय पर बर्मा जा सके और आयोगों के निष्पादन के लिए निर्धारित तिथियों पर उपस्थित हो सके।

यह बिंदु उच्च न्यायालय के समक्ष जांच के लिए आया और 23 अगस्त, 1954 को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने माना कि इस उद्देश्य के लिए अपीलकर्ता को 3000/- रुपये की राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका था, तथा कोई और धनराशि उपलब्ध नहीं थी जिससे अपीलकर्ता को उसकी इच्छा के अनुसार अतिरिक्त भुगतान किया जा सके। अपीलकर्ता की कुछ संपत्तियों और निधियों को 1944 के अध्यादेश 38 के तहत कुर्क किया गया था। अध्यादेश की धारा के तहत जिला न्यायाधीश

को कुर्क संपत्ति से जिसमें आवेदक ने हित का दावा किया था, ऐसी धनराशि प्रदान करनी थी जो आवेदक और उसके परिवार के भरण-पोषण के लिए उचित रूप से आवश्यक हो, और आवेदक की प्रतिरक्षा से जुड़े खर्चों के लिए, जहां आपराधिक कार्यवाही हो वहां किसी अनुसूचित अपराध के लिए उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही शुरू की जा सकती है। हमारा ध्यान जिला न्यायाधीश के उस आदेश की ओर आकर्षित किया गया है जिसके द्वारा उन्होंने बर्मा में गवाहों की परीक्षण के संबंध में खर्च और आगे भरण-पोषण आदि के भुगतान के लिए 3,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि अध्यादेश 38/1944 के तहत कुर्क सभी धनराशि पूरी तरह से समाप्त हो गई। उच्च न्यायालय ने भी 23 अगस्त, 1954 के अपने आदेश में पाया कि धनराशि पहले ही समाप्त हो चुकी थी और अपीलकर्ता को उसकी इच्छा के अनुसार भुगतान करने के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध नहीं थी। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता कि प्राधिकारियों की ओर से वह धनराशि प्रदान करने से इनकार कर दिया गया, जिसका अपीलकर्ता हकदार था। किसी भी मामले में, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि धनराशि उपलब्ध न कराने के बारे में यह सारी शिकायत इस तथ्य के मद्देनजर महत्वहीन है कि अपीलकर्ता ने अंततः बर्मा में उन गवाहों की परीक्षण के लिए अपना अनुरोध वापस ले लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता को बर्मा जाने में सक्षम बनाने

के लिए उसके लिए पासपोर्ट प्राप्त किया गया था, लेकिन आयोग के निष्पादन की तारीख तय होने से कुछ समय पहले पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो गई। परिणामस्वरूप, पासपोर्ट की वैधता को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजा गया था। उच्च न्यायालय ने अपील के तहत अपने फैसले में विशेष रूप से उल्लेख किया था कि, इस पासपोर्ट को नवीनीकृत करने से पहले, अपीलकर्ता ने बर्मा के गवाहों की कमीशन पर परीक्षण कराने के लिए उच्च न्यायालय से अपना अनुरोध वापस ले लिया। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होगा कि बर्मा के गवाहों से पूछताछ के लिए सभी आवश्यक कदम तब उठाए जा रहे थे जब अपीलकर्ता ने स्वेच्छा से उनसे पूछताछ के लिए अपना अनुरोध वापस ले लिया, ताकि आरोपी के बचाव में पेश होने के अधिकार से कोई इनकार न हो।

अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को भी इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि अदालत ने अपने निष्कर्षों को कुछ युद्ध डायरी पर आधारित किया था जो साक्ष्य में अस्वीकार्य थे। जिन वॉर डायरियों को उन आरोपों के संबंध में संदर्भित किया गया है, जिनके लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया है, वे 6, बॉम्बे पायनियर्स और मुख्य अभियंता, बर्कोप्रस की हैं। बाद वाले को सीई डायरीज के रूप में संदर्भित किया गया है और इन डायरियों के साथ, ऐसा प्रतीत होता है. बर्कोप्रस की सीआरई वॉर डायरीज को भी शामिल किया

गया था। हमारे सामने तर्क ये युद्ध डायरी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत साक्ष्य में स्वीकार्य थी, इसे अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित नहीं किया गया।

पहला पहलू यह रखा गया कि ये युद्ध डायरियाँ सार्वजनिक दस्तावेज नहीं थीं, वे गोपनीय थे और जनता के लिए खुले नहीं थे, और इस संबंध में, मारिया मैगिनी स्टर्ला और अन्य बनाम फिलिपो टोमासो मेटा फ्रीकिया, ऑगस्टस केपेल स्टेवेन्सन और अन्य के मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कुछ टिप्पणियों पर भरोसा किया गया था। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 की व्याख्या के लिए. इंग्लैंड में सामान्य कानून पर यह निर्णय बहुत मददगार नहीं हो सकता है, क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा 35 के तहत, स्वीकार्य दस्तावेज न केवल सार्वजनिक दस्तावेज है बल्कि आधिकारिक कृत्यों का रिकॉर्ड भी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये युद्ध डायरी, जिन्हें साक्ष्य के रूप में उपयोग किया गया है, आधिकारिक कृत्यों के रिकॉर्ड थे और वास्तव में गवाहों के विशिष्ट साक्ष्य है कि इन्हें सेना की इकाइयों पर लागू नियमों के तहत बनाए रखा जाना आवश्यक था जो इन्हें बनाए रखते थे। यह भी आग्रह किया गया कि अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध करने के लिए विशिष्ट सबूत नहीं दिए हैं कि जो व्यक्ति इन डायरियों का रखरखाव कर रहे थे, वे लोक सेवक थे। यह आपत्ति, जो पहली बार हमारे सामने उठाई गई है, इसमें तथ्य और कानून

का मिश्रित प्रश्न शामिल है। डायरियाँ सेना के अधिकारियों द्वारा रखी जाती थी और पहले किसी भी स्तर पर कोई आपत्ति नहीं की गई थी कि वे भारत सरकार के कर्मचारी नहीं थे क्योंकि वे उन इकाइयों से संबंधित थे जो भारतीय सेना का हिस्सा नहीं थे। मामला अधिनस्थ अदालतों में इस आधार पर आगे बढ़ा कि ये इकाइयाँ जिनमें ये डायरियाँ रखी गई थी, भारतीय सेना का हिस्सा थी और वास्तव में, इसी आधार पर हमारे द्वारा अपीलकर्ता की एक पूर्व आपत्ति निपटाई गई थी कि अपीलकर्ता ने कहा कि हेडरसन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक थी। इसलिए, हम इस स्तर पर इस तथ्य पर नहीं जा सकते कि क्या अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध करने के लिए सबूत पेश किए कि इन डायरियों को रखने वाले अधिकारी भारत सरकार की सेवा में थे। डायरियाँ उन व्यक्तियों के साक्ष्य से और भी सिद्ध हो गई जिन्होंने उन्हें लिखा था और उन व्यक्तियों के साक्ष्य से जिन्होंने उनमें दर्ज प्रविष्टियों को निर्देशित किया था। अतः इन डायरियों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं हुई।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि इन युद्ध डायरियों को आरोपी को तब नहीं दिया गया जब उसकी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के तहत जांच की गई और परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता के खिलाफ निष्कर्षों को रिकॉर्ड करने के लिए पूर्वाग्रह के लिए उनका उपयोग उचित नहीं था। यह

तर्क स्पष्ट रूप से 342, सी.आर.पी.सी. के प्रावधान की गलत समझ पर आधारित है। उनका प्रावधान के तहत, एक आरोपी से प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि वह अपने खिलाफ साक्ष्य में प्रस्तुत किसी भी परिस्थिति को समझाने में सक्षम हो सके, और उस उद्देश्य के लिए, अभियोजन पक्ष के गवाहों के बाद और अभियुक्त की प्रतिकक्षा से पहले आरोपी से आम तौर पर मामले पर भी पूछताछ की जाती है। ये युद्ध डायरियों अपीलकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली परिस्थितियाँ नहीं थीं। वे वास्तव में, उन परिस्थितियों के साक्ष्य थे जो आरोपी के सामने रखे गए थे जब उसकी धारा 342, सी.आर.पी.सी. के तहत जांच की गई थी। यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था कि किसी परिस्थिति के समर्थन में साक्ष्य का प्रत्येक अलग-अलग हिस्सा आरोपी के सामने रखा जाए और उससे उस धारा के तहत इसके संबंध में पूछताछ की जाए और परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने इन युद्ध डायरियों को अपीलकर्ता के विरुद्ध सबूत के हिस्से के रूप में मानने में कोई अनियमितता नहीं की।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमारे समक्ष सजा के प्रश्न से संबंधित अंतिम बिंदु रखा गया। अधिकरण द्वारा दी गई वास्तविक कारावास की सजा को उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही काफी हद तक कम कर दिया गया है और हम इसमें हस्तक्षेप के लिए कोई औचित्य नहीं हैं। यद्यपि हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित हुआ कि उच्च न्यायालय ने आरोप संख्या 21 के

संबंध में अनिवार्य जुर्माने की राशि तय करते समय एक स्पष्ट त्रुटि की। उच्च न्यायालय का निष्कर्ष यह था कि इस आरोप के तहत, दावा इस कार्य के संबंध में चार अलग-अलग मदों से संबंधित चार राशियों, अर्थात् 38,000/-रु. 44,000/-रु. 8,800/- और 17,600/- रुपये के संबंध में मिथ्या था। इस प्रकार मिथ्या दावे कुल मिलाकर रु. 1,08,400/- का था। उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा कि यह इस फर्जी दावे के संबंध में अपीलकर्ता को भुगतान की गई राशि थी और इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि दावे के संबंध में जो आरोप सख्या 21 की विषय-वस्तु थी, भुगतान वास्तव में केवल 50 प्रतिशत तक सत्यापित दावे का किया गया। इस प्रकार, मिथ्या पाए गए इस कार्य के संबंध में केवल 54,200/- रुपये की सीमा तक का भुगतान किया गया था, ना कि रुपये 1,08,400/- का। इसलिए, इस आरोप के संबंध में लगाया गया अनिवार्य जुर्माना रुपये 1,08,400/- से रु. 54,200/- तक कम किया जाना चाहिए।

जहां तक चार राज्यों की अपीलों का प्रश्न है, पंजाब राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता हमें यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं हैं कि अभियोजन पक्ष के तथ्य के निष्कर्षों को अभिलिखित करते समय उच्च न्यायालय द्वारा कानूनन कोई त्रुटि की गई है। सभी उचित संदेहों से परे यह साबित करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता को भुगतान किए गए दावे

मिथ्या थे। इसलिए, उच्च न्यायालय के निष्कर्ष में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं है।

परिणामस्वरूप, सभी अपीलें खारिज की जाती हैं। इस संशोधन के अधीन कि आरोप संख्या 21 के संबंध में अपीलकर्ता पर लगाया गया अनिवार्य जुर्माना, जो उच्च न्यायालय में 1949 की आपराधिक अपील संख्या 478 का विषय था, रु. 1,08,400/से रु. 54,200/- तक कम कर दिया गया है।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी डॉ. नेहा गोयल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।